(c) whether Government propose to construct/arrange special refrigerators to export at least 20 tonnes in one container to boost exports?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) and (b) No. Sir.

(c) The Government has no plans to construct/arrange special refrigerators to export atleast 20 tonnes in one container for mango exports. However, the Agricultural and processed Food Products Export Development Authority, APEDA, in association with the State Government agencies and leading exporters, has initiated experiments for undertaking trail shipment of managoes through Controlled Atmosphere(CA) container from selected regions for selected varieties having export potential. The success of this experiement is expected to help in enhacing the shelf life, quality of the product and its international competitiveness and thereby contribute to enhancement of export of mangoes.

Gas Cracker unit at Tengakhat, Assam

656. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many months have remained to build the Gas Cracker unit at Tengakhat, Assam as per agreement with the Reliance Company;

(b) what is the progress made till now;

(c) whether it would be commissioned in time; and

(d) the amount paid to the Reliance company for this purpose by Government?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (d) The proposed Gas Cracker unit at Tengakhat, Assam is being implemented by Reliance Assam Petro-chmeicals Ltd. (RAPL), a joint venture between Assam Industrial Development Corporation and Reliance Industries Ltd.

The Government of Assam have identified 1262 acress of land out of which 144 acres have been handed over so far to RAPL. A number of steps have been taken for finalising the Gas Supply Agreement including identification of the source of the feed-stocks, discussions on transfer price of an existing gas separation plant at Lakwa and recruitment of personnel. The project has a target date of commission in 44 months from the date of signing of Gas Supply Agreement between RAPL and OIL India Ltd. and handing over of the entire land required for the project.

The Goverment of India has not made any payments so far for the project.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादन क्षमता

657. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उपक्रमों की उत्पादन क्षमता में कमी आई है और सार्वजनिक क्षेत्र का घाटा बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता और मुनाफा बढ़ाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के उत्पादन कारी तथा विनिर्माण कारी उपक्रमों की उत्पादन क्षमता में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान कोई खास अन्तर नहीं आया है।

वर्ष 1997-98 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने कुल मिलाकर 13725.23 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, जबकि वर्ष 1996-97 के दौरान 9991.82 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों का लाभ 1996-97 के 16112.93 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 के दौरान 20266.99 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1997-98 के दौरान घाटा उठाने वाली कम्पनियों ने 6541.46 करोड़ रुपए का घाटा उठाया, जबकि गत वर्ष के दौरान 6117.41 करोड़ रुपए का घाटा उठाया था।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन तथा लाभ में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विविधीकरण तथा उत्पाद-मिश्र, कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण, तथा संयंत्र-मशीनरी का आधुनिकीकरण इत्यादि शामिल हैं।

औद्योगिकरण का विरोध

658. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः**
श्री राज मोहिन्दर सिंहः

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1999 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "मेनका अपोज्ड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश का औद्योगिकीकरण करने के स्थान पर पारंपरिक संस्कृति व उद्योगों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से देश का विकास करने की योजना को प्राथमिकता देनी चाहिये; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त करने और एक आधुनिक एंव दूरदर्शी भारत का निर्माण करने के लिए लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसे समाज का निर्माण तब ही किया जा सकता है जब यदि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के अंग के रूप में विकास करे, न कि अलग रहकर। अतः सरकार आधुनिक तथा परंपरागत उद्योगों के विकास की नीति इस प्रकार अपना रही है, जो कि देश से समग्र हित में होगी।

Industrial growth Centres in U.P.

659. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of industrial growth centres functioning in Uttar Pradesh;

(b) the details of the funds provided to these growth centres during each of the last three years;

(c) whether any study has been made of the impact of these growth centres in terms of generating employment opportunities in U.P. in general and its backward areas in particular; and

(d) if so, th details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) Under the Growth Centre Scheme seven growth centres have been approved by the Central Government for execution in Uttar Pradesh by the State Government of U.P. None of the growth centres has become fully functional yet. The details of release of funds to these centres are given in the attached statement. (*See* below)

(c) and (d) No study has been made by the Central Government of the impact of these growth centres in terms of generating employment opportunities.

Statement

Total release of Central assistance towards the seven approved growth centres at Bachauli Buzurg, Banthara, Chaudharpur, Dibiapur, Khurja, Mungra-Satharia and Sahajanwa is Rs. 2080 lakh.

During the last three years, funds have been released to the following to the extent shown against each:

Name of the growth centre	Amount released (Rs. in Lakh)		
	1995-96	1996-97	1997-98
Khurja (Bulandshahr	200	—	170